टाटा टेक्नोलाजीस के सहयोग से सेंटर आफ एक्सीलेंस बनेंगे 121 पालिटेक्निक

संस्थानों के उन्नयन पर 6935.87 करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित

कैबिनेट के फैसले

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ: प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को नई ऊंचाई मिलेगी। अब टाटा टेक्नोलाजीस लिमिटेड (टीटीएल) के सहयोग से प्रदेश के 121 राजकीय पालिटेक्निक संस्थानों को सेंटर आफ एक्सीलेंस में बदला जाएगा। इस पर कुल खर्च 6935.87 करोड़ रुपये खर्च अनुमानित है। इसमें 87 प्रतिशत यानी 6034.20 करोड़ रुपये टाटा टेक्नोलाजी वहन करेगी। शेष 13 प्रतिशत यानी 1063.96 करोड़ रुपये प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा खर्च किए जाएंगे। मशीनों और तकनीकी उपकरणों की स्थापना के लिए हर संस्थान को औसतन 57.32 करोड़ रुपये मिलेंगे। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर व मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए प्रत्येक संस्थान को 7.09 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार कुल 858.12 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है। पहले चरण में 45 पालिटेक्निक कालेजों का उच्चीकरण किया जाएगा। यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने बताया कि इससे पहले टाटा टेक्नोलाजीस के सहयोग से आइटीआइ संस्थानों का सफलतापूर्वक उच्चीकरण किया जा चुका है। अब वही माडल पालिटेक्निक संस्थानों पर लागू किया जा रहा है, जिससे तकनीकी शिक्षा का स्तर और भी ऊंचा होगा। कार्यादेश जारी होने के बाद एक वर्ष के भीतर ये सेंटर आफ एक्सीलेंस तैयार हो जाएंगे।

टाटा टेक्नोलाजीस संस्थानों को अत्याधुनिक उपकरण, स्मार्ट क्लासरूम और तकनीकी लैब उपलब्ध कराएगा, जिससे छात्रों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का भरपूर अवसर मिलेगा। उच्चीकृत संस्थानों में छात्रों को स्मार्ट आटोमेशन, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग जैसी नवीनतम तकनीकों का प्रशिक्षण मिलेगा। यह पहल केवल नौकरी दिलाने तक सीमित नहीं होगी। उच्चीकृत पालिटेक्निक कालेजों में छात्रों को स्टार्टअप शुरू करने और नवाचार के लिए तकनीकी और व्यावसायिक सहायता भी मिलेगी। यह संस्थान उद्यमिता को प्रोत्साहित करेंगे।

विधानमंडल का मानसून सत्र 11 अगस्त से

विधानमंडल का मानसून सत्र इस बार 11 अगस्त से शुरू होगा। कैबिनेट ने सत्र बुलाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इस बार सत्र की अवधि एक सप्ताह से कम रहने के आसार हैं। सरकार बजट सत्र के बाद जारी अध्यादेश व कुछ विधेयकों को मानसून सत्र में पारित कराएगी। सत्र में सीएजी की सात रिपोर्ट भी रखी जाएंगी। इन रिपोर्ट को विधानमंडल के दोनों सदनों में रखने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। नियमावली के अनुसार, एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की प्रथम बैठक के बीच अधिकतम अंतर छह माह का हो सकता है। चूंकि बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होकर पांच मार्च को स्थगित हुआ था। 12 मार्च को सत्रावसान की अधिसूचना जारी की गई थी। नियमानुसार पांच सितंबर से पूर्व नए सत्र का आयोजन हर हाल में जरूरी था। इसलिए सरकार ने 11 अगस्त से सत्र बुलाने का निर्णय लिया है। सरकार सत्रावसान के बाद जारी किए गए अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक भी मानसून सत्र में पास कराएगी।

इस बार सत्र की अवधि एक सप्ताह से कम रहने के आसार